राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

# स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........ 9511151254



@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. (UHIN/2009/34814) (epaper.swatantraprabhat.com ) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 10 जून 2026

वर्ष 16, अंक 88, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित



करोड़ों की सरकारी स्कूल भूमि पर निजी सौदे का आरोप रिकॉर्ड में नहीं दर्ज विद्यालय..03

कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर की बढ़ीं मुश्किलें,...04


# मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर भड़की कांग्रेस, सीट डकैती का आरोप

● कल ईसी के खिलाफ भूख हड़ताल

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामाकंन रद्द किए जाने के बाद से कांग्रेस भड़की हुई है. एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर सीट डकैती का आरोप लगाया है. मीडिया से बात करते हुए पटवारी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी ढोंग किया था जीतू पटवारी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामाकंन राजनीतिक रूप से रद्द किया गया. क्योंकि लीगल तरीके से वो नामांकन रद्द नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता चुना. सरकार के इस कार्य द्वारा एमपी को कलंकित किया गया. ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है. क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई करतूत ने फिर से संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का सबूत दिया है! सत्य और न्याय की इस लड़ाई को हम स्तर पर लड़ेंगे, हर हाल में जीतेंगे!

जीतू पटवारी ने आगे कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कल यानी बुधवार को सारे कांग्रेस विधायक चुनाव आयोग के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

**नामाकंन रद्द होने पर क्या बोलीं नटराजन?**

राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन रद्द होने पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि जरूरी संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार उतारने का फैसला संविधान और लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति को जाहिर करता है. उन्होंने कहा कि अब राज्यसभा और दूसरे चुनावों में पहले स्ढ्क्र मैकेनिज्म के जरिए अपनाए गए वोट-चोरी के तरीकों को दोहराने की कोशिश की जा रही है. वे भले ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हों, लेकिन उनके अपनाए गए तरीके कुछ और ही कहानी कहते हैं. नटराजन ने कहा कि एक ऐसा मामला जिस पर पहले ही संज्ञान लिया जा चुका था. हालांकि हमारे वकीलों ने सभी तर्क पेश किए, लेकिन मामले का फैसला पूरी सुनवाई के बिना ही कर दिया गया। यह साफ तौर पर उनकी नीति और मंशा को उजागर करता है. यह मुद्दा सिर्फ एक राज्यसभा सीट का नहीं है; यह मौजूदा हालात से जुड़ा है. क्या लोकतंत्र बना रहेगा और क्या भारत का संघीय ढांचा कायम रहेगा. हमारी पूरी पार्टी यहां तानाशाही थोपने की कोशिशों के खिलाफ लड़ेगी, और हम इस फैसले को चुनौती देंगे.

**इतनी फार्मालिटी भी क्यों, बीजेपी की सीट कर दें घोषित**

वकील अजय गुप्ता ने कहा कि ये पूरी तरह असंवैधानिक है. ये गुंडागर्दी वाला आदेश है. हैदराबाद के न्यायालय से मीनाक्षी जी को एक नोटिस जारी किया था. इसे उनके द्वारा बताया नहीं गया था. लेकिन हमारे जवाब में हमने उन्हें ये लिख कर दिया था. ये अपराधिक श्रेणी में नहीं आता है. उन्होंने आगे कहा कि मैं दावा करता हूं को लॉ के फर्स्ट ईयर के छात्र से भी पूछेंगे तो वो बता देगा की ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता. लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई बात नहीं सुनी. विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस तरह की दादागिरी देखने को मिली. इतनी फार्मालिटी भी क्यों की जा रही है, सीधे सीधे दिल्ली से ही सीट बीजेपी के लिए घोषित कर दें।

**बीजेपी लोकतंत्र और संविधान की कर रही हत्या**

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल नाथ ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार बहन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जाना पूरी तरह से असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है. यह घटनाक्रम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है. कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी।

**चुनाव आयोग का अस्तित्त्व भी है या नहीं?**

कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने मीनाक्षी नटराजन का नामाकंन रद्द होने पर चुनाव आयोग पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का अस्तित्व भी है या नहीं? देश में जितने भी निर्वाचित सांसद है क्या उन लोगों के खिलाफ लीगल नोटिस कभी नहीं आया. ये एक तरह से सरकार की तानाशाही है।

**कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के गेट पर दिया धरना**

उधर, इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, और भूपेश बघेल सहित कई दिग्गज नेता चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर जमा हैं. बताया जा रहा है कि सभी नेता चुनाव आयोग ऑफिस के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्हें अनुमति नहीं तो उन्होंने गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बुधवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर सकता है।

**कांग्रेस उम्मीदवार ने जानबूझकर छुपाया आपराधिक रिकॉर्ड: सीएम मोहन**

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर जानकारी छुपाई थी, यह आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने का पाप है. असल में अगर आपके खिलाफ कोई मामला हो तो यह लिखकर देना चाहिए. कांग्रेस ने जानबूझकर निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा और इसी आधार पर जो फैसला हुआ उसका मैं स्वागत करता हूं. कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए।

# 3 महीने भी नहीं टिक पाएगी तमिलनाडु में टीवीके की सरकार, स्टालिन का बड़ा दावा

● एमके स्टालिन ने दावा किया कि अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार तीन महीने भी नहीं टिक पाएगी

● उन्होंने मौजूदा सरकार की अस्थिरता पर भी सवाल उठाए और डीएमके को संघर्षशील विपक्षी दल बताया

● चेन्नई में एक कार्यक्रम में पनायूर बाबू डीएमके में शामिल हुए. स्टालिन ने डीएमके कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया, क्योंकि अब वे सत्ताधारी नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टी हैं

तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि एक्टर विजय के नेतृत्व में टीवीके की सरकार तीन महीने भी नहीं पूरी कर पाएगी। रविवार को डीएमके के विभिन्न गुटों को एकजुट करने के लिए चेन्नई के अन्ना अरिवलयम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर, तमिलनाडु लिबरेशन टाइगर्स के पूर्व विधायक पनायूर बाबू एमके स्टालिन की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए. साथ ही, पनायूर बाबू ने स्टालिन को चांदी का राजदंड भेंट किया.

कार्यक्रम में बोलते हुए स्टालिन ने कहा, 'मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मौजूदा सरकार किस तरह की है. जब इस सरकार ने पदभार संभाला था, तब मैंने कहा था कि मैं इस सरकार के बारे में 6 महीने तक बात नहीं करूंगा, लेकिन अब आशंका है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि हमें 6 महीने से पहले ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन यह सरकार इस सवाल के घेरे में चल रही है कि क्या यह 3 महीने भी टिक पाएगी? '

**टीवीके को लेकर स्टालिन का बड़ा दावा**

उन्होंने आगे कहा, 'अगर वे हमेशा एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन में जाते रहते हैं, तो वे हमेशा किसी न किसी लाभ को ध्यान में रखकर ही जाते हैं, लेकिन अब डीएमके सत्ताधारी पार्टी नहीं है. अगर आप डीएमके की तरफ आए हैं, जो अब विपक्षी पार्टी है, तो आप किसी पद के लिए नहीं आए हैं. आप काम करने, इस आंदोलन का समर्थन करने और तमिल समुदाय के लिए संघर्ष करने आए हैं।'

स्टालिन ने कहा कि इसके अलावा, हमारे लिए सफलता और असफलता बारी-बारी से आती हैं. हम सफलता को अनदेखा नहीं कर रहे हैं. हम यह साबित कर रहे हैं कि डीएमके सदस्य वह व्यक्ति है, जो असफलता से निराश हुए बिना निरंतर काम कर सकता है।

**दया पर चल रही है गठबंधन की सरकार**

उन्होंने कहा कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार अब हमारी दया पर निर्भर है. हम चुनाव जीतने और डीएमके के नेतृत्व में सरकार बनाने के इरादे से गए थे. यह सरकार आज हमारे गठबंधन की पार्टियों की दया पर चल रही है. जब हम आए, तो उन गठबंधन पार्टियों के नेताओं ने कहा कि वे हमारे गठबंधन पार्टी के नेता को बताने आए हैं. उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाइए, यह आपकी मर्जी है. मैंने उन्हें इस आधार पर भेजा था कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन नहीं आना चाहिए।

## संक्षिप्त ख़बरें

### सामुदायिक शौचालय बंद, ग्रामीण खुले में शौच को मजबूर

**भदोही।** चौरी क्षेत्र के दुरासी ग्रामसभा में लाखों रुपये की लागत से बने सामुदायिक शौचालय पर ताला लटका होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद शौचालय चालू नहीं कराया गया। खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार मौर्य ने कहा कि बंद पड़े शौचालयों की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है और जिम्मेदार प्रधान व सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

### छ्रूफिरोजाबाद ने मांगा था iPhone, दबा मामला फिर उखड़ आया

**आगरा।** फिरोजाबाद के पूर्व डीएम रमेश रंजन और पूर्व तहसीलदार टूंडला राखी शर्मा के बीच चल रहा विवाद न्यायालय पहुंच गया है। पूर्व तहसीलदार ने तत्कालीन डीएम सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इससे हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने डीआइजी और मंडलायुक्त आगरा से आख्या तलब कर अग्रिम सुनवाई के लिए 12 जून तय की है। टूंडला में तैनात रहीं तहसीलदार राखी शर्मा ने अप्रैल में फिरोजाबाद के तत्कालीन डीएम रमेश रंजन पर उत्पीड़न और अनुचित दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद तहसीलदार का ट्रांसफर हो गया था। बल्केश्वर न्यू सरस्वती नगर निवासी वर्तमान में तहसीलदार राजस्व परिषद लखनऊ के पद पर तैनात राखी शर्मा ने तत्कालीन डीएम फिरोजाबाद के खिलाफ वाद दायर करने को पत्र दिया है। इसमें अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ रमेश रंजन के अलावा डीएम फिरोजाबाद के ओएसडी शैलेंद्र शर्मा, वरिष्ठ लिपिक राजेंद्र खन्ना, वरिष्ठ लिपिक एसडीएम फिरोजाबाद अजीत उपाध्याय तथा दोजीराम वरिष्ठ लिपिक (पेशकार) डीएम कार्यालय फिरोजाबाद को भी शामिल किया है।

# सैदुलाजाब हादसे में 6 मौतों के जिम्मेदार दोनों बिल्डर गिरफ्तार, पुरानी इमारत पर 3 मंजिल और चढ़ाने से धंसी नींव

● बिल्डर मनीष खत्री और अविनाश गुप्ता सैदुलाजाब हादसे में गिरफ्तार।

● पुरानी इमारत पर अवैध निर्माण से 6 लोगों की मौत हुई।

● कमजोर नींव पर तीन अतिरिक्त मंजिलें बनाने से इमारत ढही।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**दक्षिणी दिल्ली।** सैदुलाजाब हादसे में फरार चल रहे दोनों आरोपित बिल्डर को महरौली थाने की पुलिस ने मंगलवार को वसंत कुंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बिल्डर मनीष खत्री और अविनाश गुप्ता इमारत पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करा रहे थे। मामले में भवन स्वामी करमवीर जेलदार को पुलिस एक जून को ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। घटना में छह लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं आठ लोग घायल हुए थे। दोनों गिरफ्तार आरोपितों को पुलिस बुधवार को साकेत कोर्ट में पेश करेगी।

**तीसरे तल का चल रहा था काम**

जानकारी के मुताबिक व्यावसायिक इमारत चार तल की थी। इसके ऊपर तीन और तल बनाए जा रहे थे। आरोपित भवन स्वामी करमवीर को उसके कुछ परिचितों ने कमजोर हो चुकी 400 वर्ग गज में बनी 15 वर्ष पुरानी चार मंजिला इमारत को तोड़कर नए सिरे से निर्माण की सलाह दी थी। पर वह नहीं माना। बिल्डर मनीष और अविनाश को काम सौंप दिया। चार मंजिला इमारत के ऊपर दो तल बन चुके थे और तीसरे तल का काम चल रहा था।

**कमजोर नींव नहीं झेल सकी वजन**

30 मई को कमजोर नींव लोड पाकर फट गई और पूरी इमारत ढह गई। मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। बचाव व राहत कार्य में लगे फायर ब्रिगेड के अधिकारी के मुताबिक, मलबा हटाने के दौरान पता चला की ऊपरी मंजिल हाल-फिलहाल ही बने थे, जिन पर सीमेंट की लिपाई तक नहीं हो पायी थी।

**खाना खा रहे लोग मलबे के नीचे गए थे दब**

गली नंबर पांच में इमारत अराइज कोचिंग और कैंटीन के बीच में थी। कैंटीन की छत का अगला हिस्सा टिन शेड था, जबकि पीछे एक कमरा पक्का था। हादसे के समय अराइज कोचिंग के साथ ही आस-पास रहने वाले कुछ छात्र खाना खा रहे थे। इमारत का मलबा इस ढाबे की छत पर जा गिरा। इससे खाना खा रहे लोग मलबे के नीचे दब गए थे।

# कैंसर अधिसूचित करने लायक बीमारी नहीं... सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र का जवाब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कैंसर को संक्रामक रोगों की तरह अनिवार्य रूप से अधिसूचित करने लायक बीमारी नहीं है. ना ही ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि यह एक गैर-संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है. केंद्र ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कही है. दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अनुराग श्रीवास्तव की रिट याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल किया है. याचिका में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कैंसर को अधिसूचित बीमारी की सूची में डालने और निगरानी से संबंधित उपायों की मांग की गई है. जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) संक्रामक रोगों के लिए बनाई गई अनिवार्य अधिसूचना प्रणाली के बजाय कैंसर को रजिस्टर करने और दीर्घकालिक महामारी विज्ञान के तहत निगरानी की सिफारिश करता है. वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया और कहा कि देश में कैंसर रोग को प्रबंधित करने के लिए मौजूदा तंत्र वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त और संवैधानिक रूप से अनुपालन योग्य हैं।

**कैंसर स्वास्थ्य संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय**

केंद्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि कैंसर संक्रामक नहीं है और इससे सामुदायिक प्रसार का कोई खतरा नहीं है. हलफनामे में कहा गया है कि स्वास्थ्य संविधान के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य का विषय है, और रोग अधिसूचना संबंधी निर्णय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों या कार्यकारी आदेशों के तहत कैंसर को निगरानी के लिए अधिसूचित कर दिया है. जबकि आईसीएमआर द्वारा राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (NCRP) और संबंधित जनसंख्या-आधारित और अस्पताल-आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी कैंसर निगरानी पहले से ही की जा रही है।

**नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करने का आग्रह**

सरकार ने हलफनामे में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD), आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, राज्य कैंसर संस्थान और तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र समेत मौजूदा समय चल रही कई पहलों पर प्रकाश डाला और कहा कि ये कार्यक्रम कैंसर की रोकथाम, स्क्रीनिंग, निदान और उपचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

# घरेलू सिलिंडर 29 रुपये महंगा, 3 माह फिर महंगी हुई रसोई गैस; चेक करें आगरा का नया रेट

● घरेलू सिलेंडर के दाम में 29 रुपये की वृद्धि।

● आगरा में नया मूल्य अब 954.50 रुपये हुआ।

● नई दरें 7 जून से प्रभावी, तीन माह बाद बढ़ोतरी।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आगरा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार रात घरेलू सिलेंडर के रेट में बढ़ोत्तरी कर दी है। 3 माह के बाद 29 की बढ़ोत्तरी की गई है। सिलिंडर का नया मूल्य 954 रुपए 50 पैसे हो गया है। नए रेट 7 जून से प्रभावित हो गए। माह की पहली तारीख को कमर्शियल सिलिंडर के रेट में हर माह बढ़ोतरी हो रही है लेकिन 7 मार्च के बाद से घरेलू सिलिंडर के रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है।

**आगरा में अब 954 रुपए 50 पैसे हो गया नया रेट**

शनिवार रात पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिलिंडर के रेट में 29 रुपए बढ़ा दिए। सिलिंडर का नया रेट 954 रुपए 50 पैसे हो गया है। इससे पूर्व सिलिंडर का रेट 925 रुपए 50 पैसे था। वही कमर्शियल सिलेंडर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।

**आगरा में 84 गैस एजेंसियां**

वर्तमान में जिले में 84 गैस एजेंसियों में 56 आईओसी की हैं। 13.57 लाख में सात लाख उपभोक्ता आईओसी के हैं। घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक और कदम उठाया है। पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा गया है। पीएनजी उपभोक्ता घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग नहीं कर सकते हैं। न ही सिलेंडर ले सकते हैं।

# बेखौफ दौड़ रहे ओवरलोड डंपर, शहर की सड़कों पर मंडरा रहा हादसों का खतरा

● गिट्टी-बजरी से लदे वाहनों पर नहीं लग रही लगाम

● घनी आबादी वाले इलाकों में तेज रफ्तार से बढ़ी लोगों की चिंता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**ललितपुर।** मुख्यालय की सड़कों पर इन दिनों गिट्टी और बजरी से भरे ओवरलोड डंपरों का संचालन आम बात हो गया है। दिन हो या रात, शहर के व्यस्त और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरते ये भारी वाहन न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि किसी बड़े हादसे की आशंका भी लगातार बढ़ा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्धारित क्षमता से अधिक माल भरकर चल रहे डंपर तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों की जान जोखिम में पड़ रही है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर गिट्टी और बजरी से लदे डंपरों के गुजरने के दौरान अक्सर सामग्री सड़क पर गिरती देखी जा सकती है। सड़क पर बिखरी गिट्टी के कारण बाइक और साइकिल सवारों के फिसलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ललितपुर में चल रहे निर्माण कार्यों और खनन क्षेत्रों से आने-जाने वाले डंपरों की संख्या लगातार बढ़ी है। शहर में प्रवेश करने वाले अनेक डंपरों में सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जाता। कई वाहनों पर तिरपाल तक नहीं ढका जाता, जिससे रास्ते भर गिट्टी और धूल उड़ती रहती है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है बल्कि पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया पर भी आए दिन ओवरलोड डंपरों के वीडियो और तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। कई बार नागरिकों द्वारा प्रशासन और संबंधित विभागों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद व्यापक स्तर पर कार्रवाई दिखाई नहीं देती। इससे लोगों में यह धारणा बन रही है कि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों को अप्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओवरलोड वाहन सड़क की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। भारी भार के कारण सड़कें समय से पहले क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे सरकार को मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। वहीं नगरवासियों का कहना है कि परिवहन, खनन और यातायात विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों की जांच करनी चाहिए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

# डेमोग्राफी बदलाव भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

जनसांख्यिकीय बदलाव के कारणों के अध्ययन, अवैध प्रवासन की जांच और समाधान हेतु भारत सरकार ने हाल ही में जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर रही है। इसके अतिरिक्त, डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभांश) का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं. डीसीयुवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है।रोजगार और उद्यमिता और मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।शिक्षा : नई शिक्षा नीति 2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

आपको बता दें डेमोग्राफिक चेंज पर केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार का घेराव किया था। इसी आधार पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मात दी और पूर्व बहुमत से सत्ता हासिल की। ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी गठित करना अहम माना जा रहा है।

डेमोग्राफिक चेंज पर केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (26 मई 2026) को इसकी घोषणा की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफिक चेंज पर 'हाई लेवल कमेटी' बनाने की घोषणा की थी.

गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है. जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा (रिटायर्ड आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव (रिटायर्ड आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे. संयुक्त सचिव (फॉरेनर्स-I), गृह मंत्रालय, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।'

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ बड़ा मुद्दा था. इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार का घेराव किया था. इसी आधार पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मात दी और पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की. ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी गठित करना अहम माना जा रहा है। आपको याद हो कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 कहा था कि भारत अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए जनसांख्यिकीय मिशन शुरू करेगा. उन्होंने लोगों को अवैध घुसपैठ के माध्यम से देश की जनसांख्यिकी को बदलने की सोची-समझी साजिश के बारे में चेतावनी दी और कहा कि कोई भी राष्ट्र घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की.उनहोने कहा था आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं. षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है. एक नए संकट के बीच बोए जा रहे हैं और यह घुसपैठिए, मेरे देश के नौजवानों के रोजी-रोटी छीन रहे हैं. यह घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। यह घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. यह

देश सहन नहीं करेगा और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है. देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए यह संकट पैदा करता है। सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है. दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है। हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य हैं कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसलिए मैं आज लाल किले को प्राचीर से कहना चाहता हूं। हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है. यह मिशन, इस मिशन के द्वारा यह जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पर मंडरा रहा है यह जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

भारत में धर्म के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत लगातार हिन्दू आबादी के गिरावट होने का संकेत देता है 1951, 2011, 2001

1991 1981 1971
1961 ह1951
**हिंदू-** 4.30% 79.80%
80.50% 81.50% 82.30%
82.70% 83.50% 84.10%
**मुस्लिम** 4.40% 14.20%
13.40% 12.60% 11.80%
11.20% 10.70% 9.80%।

1951 से 2011 तक की जनगणना में जो सभी धर्मों की जनसंख्या वृद्धि में असमानता दिखती है, उसका प्रमुख कारण घुसपैठ है. इस देश में 1951, 1971, 1991 और 2011 में जनगणना हुई, जिनमें शुरू से ही धर्म पूछने की परंपरा रही है. 1951 की जनगणना में हिंदू आबादी 84 प्रतिशत थी, जबकि मुस्लिम आबादी 9.8 प्रतिशत थी. 1971 में हिंदू आबादी 82 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 11 प्रतिशत हो गई. 1991 में हिंदू आबादी 81 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 12.2 प्रतिशत हो गई।

वहीं, 2011 में हिंदू आबादी 79 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 14.2 प्रतिशत हो गई. मुस्लिम आबादी में 24.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5 प्रतिशत की कमी आई है. मोदी सरकार की घुसपैठ विरोधी 3डी नीति- पहचान करना मतदाता सूची से हटवाना, उन्हें वापस भेजना है। सबसे गौरतलब बात है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी हिंदू आबादी की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है. साल 2010 में 14.4% से बढ़कर 2050 में 18.4% होने का अनुमान है।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि झारखंड की आदिवासी आबादी में गिरावट के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठ का हाथ है. उन्होंने मांग की थी कि राज्य के कुछ हिस्सों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों और बिहार के किशनगंज और कटिहार को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए ताकि क्षेत्र में 'बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों' की बढ़ती संख्या से उत्पन्न चुनौती से निपटा जा सके, जिसके कारण, उनके अनुसार, आदिवासी आबादी में काफी कमी आई है। उन्होंने ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के कारण घट रही है. उन्होंने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी 2000 में 36% थी, जो अब घटकर 26% रह गई है. उन्होंने पूछा, 'ये आदिवासी कहां चले गए?'2014 से, भारत की सीमाओं पर घुसपैठ के 8,500 से अधिक प्रयासों का पता चला है, जबकि 20,000 से अधिक घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है।

भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर सुरक्षा, अर्थशास्त्र और नीति निर्माण के स्तर पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। केंद्र सरकार और सुरक्षा विश्लेषकों का एक वर्ग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती मानता है, जबकि अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकी विशेषज्ञ इसे गिरती प्रजनन दर और बुजुर्ग होती आबादी से जुड़ी आर्थिक चुनौती के रूप में देखते हैं।इस विषय को मुख्य रूप से अलग-अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से समझा जा सकता है: सुरक्षा और सामाजिक संतुलन का दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण के तहत, देश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, विशेषकर सीमावर्ती इलाकों में हो रहे 'अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय बदलाव' को एक बड़ा खतरा माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, अवैध घुसपैठ और अनियमित प्रवासन के कारण सीमावर्ती राज्यों (जैसे असम, पश्चिम बंगाल, और बिहार) की जनसंख्या बनावट में असामान्य बदलाव आए हैं, जो कानून-व्यवस्था और संप्रभुता के लिए चिंता का विषय हैं।सरकार को गंभीरता से सख्त कदम उठाने चाहिए।

**मनोज कुमार अग्रवाल**

# रील की लत से बीमार होता युवा

**संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला**

सोशल मीडिया पर रील का बुखार दिन रात बढ़ता जा रहा है ऐसे में वो युवा वर्ग जिसने रील को ही अपना कैरियर मान लिया है बीमार होता जा रहा, 15 सेकंड की रील के कारण अनगिनत बीमारी का शिकार होता जा रहा है। इस पर शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाने होंगे नहीं तो स्थिति आगे चलकर बहुत बिगड़ सकती है। पहले हम खाना खाते वक्त बात करते थे। अब खाना ठंडा हो जाता है, लेकिन रील नहीं रुकती। 15 सेकंड की वीडियो ने युवा दिमाग को ऐसे पकड़ा है कि घंटों निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। रील्स डोपामिन का शॉर्टकट हैं। हर नई वीडियो पर दिमाग को छोटा सा 'रिवॉर्ड' मिलता है। असल जिंदगी की मेहनत वाले काम - पढ़ाई, प्रोजेक्ट, रिश्ते - में रिजल्ट देर से मिलता है। दिमाग आसान वाला रास्ता चुन लेता है। ध्यान का बिखराव- 2 मिनट से ज्यादा एक काम पर टिकना मुश्किल लगने लगता है। नींद का बिगड़ना रात 2 बजे तक स्क्रॉल करना और सुबह उठ न पाना आम हो गया है

तुलना का जहर- दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी फीकी लगने लगती है। लक्षण जो दिखने लगे हैं- यह सिर्फ 'टाइम वेस्ट' नहीं रहा। अब ये मानसिक सेहत पर दिखने लगा है। बिना वजह चिड़चिड़ापन और बेचैनी जब फोन पास न हो- अकेले बैठे रहना, दोस्तों से मिलने का मन न करना

- पढ़ाई या काम में रुचि कम होना, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ना, आत्मविश्वास में गिरावट क्योंकि हर कोई 'परफेक्ट' लग रहा है। कई युवा खुद कहते हैं - 'पता है नुकसान हो रहा है, पर छोड़ नहीं पाता '। यही लत की निशानी है। अगर तुमने एक बार सैड वीडियो देखी, तो अगले 20 वीडियो उसी मूड की होंगी। तुम्हारा कंट्रोल कम, प्लेटफॉर्म का कंट्रोल ज्यादा।

दूसरा कारण है खालीपन। असली उपलब्धि, मेहनत, बातचीत में टाइम लगता है। रील्स तुरंत एंटरटेनमेंट देती हैं। खाली दिमाग सबसे पहले वहीं जाता है।

इससे निकलने का रास्ता बहुत ही आसान है लेकिन लोग प्रयास ही नहीं करते। पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, पर कंट्रोल वापस लेना जरूरी है। स्क्रीन टाइम को देखो- फोन में ही पता चल जाता है कितना वक्त जा रहा है। नंबर देखकर झटका लगता है। रील के लिए टाइम फिक्स करो- दिन में 20 मिनट, बस। बाकी टाइम ऐप लॉक कर दो। रिप्लेसमेंट ढूंढो- जो खालीपन रील भरती है, उसे किताब, जिम, दोस्ती, कोई स्किल से भरो। खाली मत छोड़ो।

नोटिफिकेशन बंद करो- हर नॉटिफिकेशन दिमाग को खींचता है। हिम्मत करके बंद कर दो। हाथ से फोन दूर रखो सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद फोन मत छुओ। इसके लिए अपने आप से ही सवाल करना होगा। रील देखकर तुम्हें क्या मिल रहा है? 1 घंटे बाद कैसा महसूस होता है - रिलैक्स या खालीपन। अगर जवाब 'खालीपन' है, तो समझो ये एंटरटेनमेंट नहीं, एस्केप है। दिमाग एक मसल है। अगर तुम उसे सिर्फ 15 सेकंड के शॉट्स खिलाओगे, तो वो लंबी रेस नहीं दौड़ेगा। कॉलेज, करियर, रिश्ते - सब लंबी रेस हैं।

रील बुरा नहीं है। बुरा है जब रील तुम्हारी जिंदगी चला रही हो। कंट्रोल वापस लो, वरना 5 साल बाद पछतावा ज्यादा और समय कम बचेगा। तुम्हारे हिसाब से रील्स पर सबसे ज्यादा टाइम कहां चला जाता है - एंटरटेनमेंट, इंफो, या बस स्क्रॉल करने की आदत में। आज के दौर में सोशलमीडिया पर मानसिक स्वास्थ्यक्षको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक बातों को रील के जरिये 30 सेकंड के

वायरल कंटेंट में बदल दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका नतीजा यह हो रहा है कि युवा पीढ़ी थेरेपी स्पीक में घिरती चली जा रही है, लेकिन असली खतरनाक है 30 सेकंड की रील थेरेपी

विशेषज्ञों के अनुसार, सोशल मीडिया पर 30 सेकंड की रील देखने या इंस्टाग्राम पोस्ट को कोट करने से किसी व्यक्ति की मानसिक परेशानी या अंदर की भावनात्मक उलझन ठीक नहीं हो जाती। रील ने गंभीर मनोवैज्ञानिक बातों को एक बिकने वाली चीज बना दिया है। भावनात्मक समझ के मामले में वे

कमजोर होते जा रहे हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1,055 जेन-जी पर एक सर्वे किया

गया। इसमें हर चार में से एक युवा ने माना कि एक महीने में उनके अच्छे दिनों के मुकाबले बुरे दिन ज्यादा होते। हैं। काम करने वाले लगभग 40 फीसदी

युवा यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें हर हफ्ते कई बार गंभीर चिंता या डिप्रेशन के लक्षण महसूस होते हैं। पिछली पीढ़ियों के मुकाबले आज के युवाओं में

तनाव या अवसाद की बात खुलकर स्वीकार करने और मदद मांगने की। संभावना सबसे ज्यादा देखी गई है।

# कोकरोच जनता पार्टी- एक नाम नहीं, एक पीढ़ी का सवाल

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अनेक ऐसे क्षण आए हैं जब व्यवस्था के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ ने अचानक राष्ट्रीय विमर्श का रूप ले लिया। कभी यह आवाज़ किसान आंदोलनों के रूप में सामने आई, कभी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के रूप में और कभी युवाओं की आकांक्षाओं के रूप में। जंतर-मंतर पर दिखाई दिया कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी उसी परंपरा की एक नई कड़ी प्रतीत होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जन्म किसी पारंपरिक राजनीतिक संगठन से नहीं, बल्कि व्यंग्य, सोशल मीडिया और युवाओं की निराशा से हुआ। यही कारण है कि इसे केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि समकालीन भारत की सामाजिक मनोदशा के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए।

कुछ समय पहले तक 'कोकरोच जनता पार्टी' नाम को अधिकांश लोग एक इंटरनेट व्यंग्य के रूप में देखते थे। किंतु इतिहास बताता है कि कई बार व्यंग्य ही सबसे गंभीर राजनीतिक प्रश्नों को जन्म देता है। व्यंग्य व्यवस्था की उन कमजोरियों को उजागर करता है जिन्हें सामान्य राजनीतिक भाषा अक्सर छिपा देती है। कोकरोच का प्रतीक भी इसी कारण महत्वपूर्ण है। यह उस जीव का प्रतीक है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। आंदोलन से जुड़े युवाओं ने इसे उस भारतीय नागरिक का रूपक बनाया जो लगातार चुनौतियों, अनिश्चितताओं और निराशाओं के बावजूद अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता रहता है।

जंतर-मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार संस्थानों ने रिपोर्ट किया कि बड़ी संख्या में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और युवा प्रदर्शन में शामिल हुए। उनकी मांगों का केंद्र शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, परीक्षा प्रबंधन की जवाबदेही और युवाओं के भविष्य से जुड़े प्रश्न थे। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। यह मांग केवल किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि उस व्यापक भावना का प्रतीक थी जिसके अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही शीर्ष स्तर तक दिखाई देनी चाहिए। इस आंदोलन को समझने के लिए भारत के वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को समझना आवश्यक है। भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। हर वर्ष करोड़ों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। उनके लिए यह परीक्षाएँ केवल नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक उम्मीदों का केंद्र होती हैं। अनेक परिवार अपनी सीमित आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर खर्च करते हैं। ऐसे में जब परीक्षा प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठते हैं, पेपर लीक की घटनाएँ चर्चा में आती हैं या भर्ती प्रक्रियाएँ वर्षों तक लंबित रहती हैं, तब उसका प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी होता है।

युवाओं के बीच बढ़ते असंतोष की जड़ें केवल एक परीक्षा या एक विवाद तक सीमित नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में रोजगार, भर्ती प्रक्रियाओं की गति, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और अवसरों की समानता को लेकर व्यापक बहस होती रही है। एक ओर देश तकनीकी विकास, डिजिटल क्रांति और आर्थिक प्रगति की बात करता है, दूसरी ओर लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का अनुभव करते हैं। यही विरोधाभास इस आंदोलन की ऊर्जा का स्रोत बनता दिखाई देता है।

कोकरोच जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने युवाओं की इस बेचैनी को एक प्रतीकात्मक भाषा दी। पारंपरिक राजनीतिक दल अक्सर युवाओं की समस्याओं को चुनावी वादों तक सीमित कर देते हैं, किंतु यह आंदोलन प्रश्नों को केंद्र में रखता है। यह पूछता है कि यदि शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास कमजोर पड़ रहा है तो उसे पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है। यदि भर्ती प्रक्रियाओं में देरी होती है तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। यदि लाखों युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं, तो उनके समय और श्रम का मूल्यांकन कैसे होगा। ये प्रश्न किसी दल विशेष के नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की गुणवत्ता से जुड़े प्रश्न हैं। इस आंदोलन का एक मनोवैज्ञानिक आयाम भी है। आधुनिक युवा केवल नौकरी नहीं चाहता, वह निष्पक्ष अवसर चाहता है। वह केवल चयन नहीं चाहता, बल्कि यह भरोसा भी चाहता है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण है। यदि यह भरोसा कमजोर पड़ता है, तो सामाजिक निराशा बढ़ती है। यही कारण है कि जंतर-मंतर पर दिखाई दिया विरोध केवल प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस अविश्वास के विरुद्ध भी था जो धीरे-धीरे संस्थाओं के प्रति विकसित हो सकता है।

लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो ऐसे आंदोलन व्यवस्था के लिए चेतावनी नहीं बल्कि अवसर होते हैं। वे बताते हैं कि समाज के किस हिस्से में असंतोष जमा हो रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यदि कोई सरकार या प्रशासन इन संकेतों को समय रहते समझ ले, तो कई समस्याओं का समाधान संवाद और सुधार के माध्यम से किया जा सकता है। जंतर-मंतर का प्रदर्शन इसी प्रकार का लोकतांत्रिक संकेत था। यह आक्रोश का प्रदर्शन अवश्य था, किंतु उससे अधिक यह जवाबदेही की मांग थी।

राजनीतिक विश्लेषण के स्तर पर यह आंदोलन एक और महत्वपूर्ण संकेत देता है। भारतीय राजनीति लंबे समय तक पहचान आधारित मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, किंतु नई पीढ़ी के लिए शिक्षा, रोजगार, कौशल, अवसरों की समानता और संस्थागत दक्षता जैसे विषय तेजी से केंद्रीय मुद्दे बनते जा रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में राजनीति की प्राथमिकताएँ भी बदल सकती हैं। तब चुनावी विमर्श केवल भावनात्मक मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक प्रदर्शन और संस्थागत विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण कारक बनेंगे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि इसने राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बदलने का प्रयास किया है। इसने यह संदेश दिया है कि युवा केवल दर्शक नहीं रहना चाहते। वे अपने भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे, भर्ती प्रक्रियाएँ समयबद्ध और पारदर्शी हों तथा अवसरों का वितरण निष्पक्ष हो। ये मांगें किसी विशेष विचारधारा की नहीं, बल्कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी अपेक्षाएँ हैं।

**अंततः** कोकरोच जनता पार्टी की कहानी व्यंग्य से आंदोलन तक पहुँचने की कहानी भर नहीं है। यह उस पीढ़ी की कहानी है जो अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपने भविष्य के लिए जवाब मांग रही है। यह उस लोकतांत्रिक ऊर्जा की कहानी है जो सोशल मीडिया के एक प्रतीक से निकलकर सड़कों तक पहुँच गई। इसे केवल विरोध के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकेत के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यदि व्यवस्था इस संकेत को समझती है, तो यह आंदोलन केवल एक दिन की खबर नहीं रहेगा, बल्कि उन सुधारों की शुरुआत का आधार बन सकता है जिनकी मांग आज लाखों युवा कर रहे हैं। लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि वह ऐसी आवाज़ों को सुन सके, उनसे संवाद कर सके और उन्हें परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा बना सके।

**अवनीश कुमार गुप्ता**

# 27 साल पुरानी फिल्म का सीक्वल लाने की तैयारी में सुभाष घई, यंग एक्टर्स को करेंगे कास्ट?

**नई दिल्ली।** इतने सालों बाद भी ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना की फिल्म ताल कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। सुभाष घई इस फिल्म के निर्देशक थे और सिने प्रेमियों के दिल में इसके लिए खास जगह है।

अब,घई इस लोकप्रिय रोमांटिक फिल्म का सीक्वल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने फैंस को इसका हिंट दिया और उनसे एक सवाल भी पूछा। सुभाष घई ने लोगों से सवाल पूछा कि क्या उन्हें ताल 2 (ज्ञ्ङ्गड्डद्य 2) एक नई कास्ट के साथ बनानी चाहिए या फिर वो पुरानी कास्ट को ही देखना पसंद करेंगे?

अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, फिल्म निर्माता ने यह भी बताया कि उन्हें ताल के लिए अब तक की सबसे बड़ी तारीफ क्या मिली थी। उन्होंने बताया कि शिकागो में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान, एक मशहूर हॉलीवुड समीक्षक ने इसे शुद्ध मनोरंजन और मासूमियत कहा था।

# दैनिक राशिफल

**मेष** आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

**वृषभ** धैर्य और समझदारी से काम लेने का दिन है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

**मिथुन** करियर में प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। यात्रा के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

**कर्क** भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

**सिंह** मान-सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापारियों को लाभ मिलने के संकेत हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

**कन्या** नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।

**तुला** भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

**वृश्चिक** कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

**धनु** नई संभावनाएं सामने आएंगी। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

**मकर** मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

**कुंभ** रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। करियर में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

**मीन** आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में लाभ के योग हैं। पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

# क्या पुतिन ने एक वाक्य में बदलती दुनिया का सच कह दिया?

**[ रिश्तों की असली मुद्रा भरोसा होती है, रूस ने वही निवेश किया ]**

**[ रूस की आँखों में भारत: भरोसा, संतुलन और आने वाला भविष्य ]**

इतिहास के कठिन दौर ही रिश्तों की असली परीक्षा लेते हैं। ऐसे समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत को 'दुनिया के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक' बताना महज़ कूटनीतिक वाक्य नहीं है। 4 जून 2026 को सेंट पीटर्सबर्ग में दिया गया उनका बयान ऐसे समय आया, जब यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया नए राजनीतिक खाँचों में बँटती दिख रही है। प्रतिबंधों से घिरा रूस अपने विश्वसनीय मित्रों को पहचान रहा है और भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से अलग सम्मान पा रहा है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत पर पश्चिमी दबाव को 'निष्फल और प्रतिकूल' बताया। यह केवल मित्रता की प्रशंसा नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत के बढ़ते महत्व की स्वीकारोक्ति है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शब्द अक्सर परिस्थितियों का आईना होते हैं। पुतिन की भारत-प्रशंसा को भी इसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस पश्चिमी प्रतिबंधों और राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे समय में भारत उन विरले देशों में रहा, जिसने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार रूस से संबंध बनाए रखे। न उसने किसी दबाव के आगे झुकना स्वीकार किया, न अपनी विदेश नीति का मार्ग बदला। पुतिन भलीभांति समझते हैं कि भारत जैसा मित्र केवल आर्थिक सहयोगी नहीं, बल्कि कूटनीतिक संबल भी है। इसलिए उनका यह बयान प्रशंसा से अधिक उस विश्वास की अभिव्यक्ति है, जिस पर रूस भविष्य की अपनी रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार देखता है।

पुतिन के बयान का एक संभावित संकेत चीन की ओर भी है। रूस और चीन भले ही अटूट साझेदारी का दावा करें, लेकिन उनके संबंधों में रणनीतिक सतर्कता बनी रहती है। चीन की बढ़ती आर्थिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति ने एशिया का शक्ति-संतुलन बदल दिया है। मॉस्को समझता है कि बीजिंग पर अत्यधिक निर्भरता उसकी स्वतंत्र भूमिका को सीमित कर सकती है। ऐसे में भारत के साथ मजबूत संबंध उसे संतुलन देते हैं। यही कारण है कि पुतिन ने ब्रह्मोस, रक्षा सहयोग और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी साझेदारी का विशेष उल्लेख किया। इसे मुख्य रूप से चीन के विरुद्ध संदेश न मानकर, एशिया में शक्ति-संतुलन साधने की रूस की दीर्घकालिक कूटनीतिक रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी पहचान उसकी स्वतंत्रता है। यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत पर पड़ रहे अमेरिकी दबाव के बीच उसकी नीति की सराहना की। अमेरिका लंबे समय से रूस से जुड़े ऊर्जा और रक्षा संबंधों को लेकर भारत को अपने अधिक निकट लाने का प्रयास करता रहा है। इसके

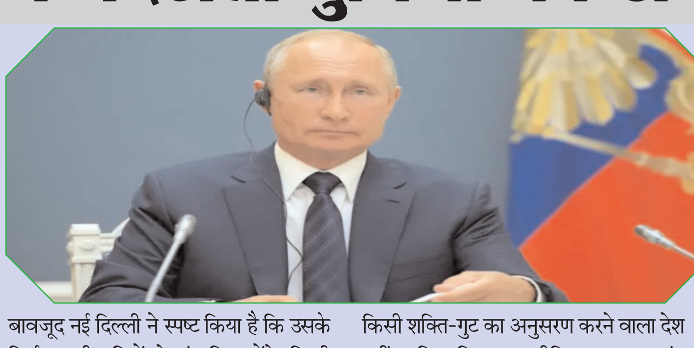

बावजूद नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि उसके निर्णय राष्ट्रीय हितों से संचालित होंगे, किसी बाहरी दबाव से नहीं। पुतिन ने इसी आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत जैसे उभरते राष्ट्र पर दबाव डालना उलटा पड़ सकता है। उनका संदेश केवल वाशिंगटन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था कि भारत अब अपनी राह स्वयं तय करने वाली शक्ति है।

आज भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक शक्ति उसका संतुलित और स्वतंत्र दृष्टिकोण है। भारत एक ओर रूस से ऊर्जा, रक्षा उपकरण और सामरिक सहयोग प्राप्त कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ तकनीक, निवेश और सुरक्षा साझेदारी भी मजबूत कर रहा है। चीन से प्रतिस्पर्धा के बावजूद व्यापारिक संबंध भी बने हुए हैं। यही संतुलन भारत को वैश्विक राजनीति में अलग पहचान देता है। पुतिन ने मोदी सरकार की आर्थिक उपलब्धियों और तेज विकास दर की सराहना करते हुए संकेत दिया कि भारत अब किसी शक्ति-गुट का अनुसरण करने वाला देश नहीं, बल्कि विश्व राजनीति का एक स्वतंत्र और प्रभावशाली शक्ति केंद्र बन चुका है। भारत-रूस संबंध अब केवल कूटनीति तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी नई मजबूती हासिल कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार लगभग 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें रूसी तेल, गैस और कोयले की प्रमुख भूमिका रही। पुतिन द्वारा 100 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य का उल्लेख इस बात का संकेत है कि रूस भारत को केवल मित्र नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक साझेदार मानता है। ऊर्जा, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग, रक्षा उत्पादन और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच दोनों देश एक-दूसरे की क्षमताओं को अपने विकास का महत्वपूर्ण आधार मान रहे हैं। मित्रता जितनी गहरी होती है, उसकी चुनौतियां भी उतनी ही वास्तविक होती हैं। भारत-रूस संबंधों के सामने भी व्यापार असंतुलन, भुगतान व्यवस्था की बाधाएं, रक्षा खरीद में भारत की नई प्राथमिकताएं और रूस-चीन की बढ़ती निकटता जैसे प्रश्न मौजूद हैं। इसलिए पुतिन ने भारत-चीन सीमा पर तनाव कम करने के प्रयासों का स्वागत किया। यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि रूस का यह संदेश था कि वह एशिया में स्थिरता और संतुलन का पक्षधर है। साथ ही, वह यह भरोसा भी दिलाना चाहता है कि चीन से उसके संबंध भारत के हितों की कीमत पर नहीं हैं। भारत के लिए यह आश्वासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी विदेश नीति का आधार केवल राष्ट्रीय हित हैं। विश्व राजनीति में कुछ वक्तव्य तत्कालीन घटनाओं से आगे जाकर भविष्य की दिशा भी बताते हैं। पुतिन का भारत को 'भरोसेमंद साझेदार' कहना ऐसा ही संकेत है। यह केवल भारत-रूस संबंधों की निकटता नहीं, बल्कि आकार ले रही नई वैश्विक व्यवस्था की झलक है। एकध्रुवीय प्रभुत्व का दौर पीछे छूट रहा है और नई शक्तियां उभर रही हैं। ब्रिक्स का विस्तार, वैश्विक दक्षिण का बढ़ता प्रभाव और भारत की भूमिका इसी परिवर्तन के संकेत हैं। रूस का यह सार्वजनिक विश्वास एक स्पष्ट संदेश देता है—भारत अब किसी समीकरण का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं एक निर्णायक समीकरण है। इसलिए पुतिन का यह बयान केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। **प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'**

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

## संक्षिप्त खबरें

### विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्काउट और गाइड द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया

**लखनऊ।** राजधानी लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 के अवसर पर विद्यालय में भारत स्काउट गाइड, जिला संस्था के तत्वावधान में हनुमान प्रसाद रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सभी नें एक पेड़ मां के नाम लगाया एवं त्रिदिवसीय पर्यावरण कार्यशाला में बच्चों के द्वारा बेकार चीजों से बनाए गए सुंदर गमले एवं बच्चों द्वारा बनाए गए थैलों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ0 आर.पी. मिश्रा, जिला संरक्षक भारत स्काउट गाइड ने की सभी प्रतिभागी बच्चों को एक-एक पौधा भेंट किया गया। आरती वर्मा को ग्रीन क्लास टीचर का पुरस्कार दिया गया। गीता देवी को बच्चों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की मसाल गाइड कंपनी की कप्तान मीता श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के पर्यावरण क्लब की शिक्षिकाएं रेनू वर्मा, डॉ0 सुमन दुबे, गीता देवी एवं हरजीत कौर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला सचिव अनिल शर्मा विद्यालय के प्रबंधक कृष्ण जीवन रस्तोगी एवं उपाध्यक्ष ईंद्रप्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहे। डॉ0 आर पी मिश्रा ने बच्चों के द्वारा बनाए गए सुंदर प्लांटर्स की प्रशंसा की एवं फलदार आम का वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया।

### मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक मनाया

**मिश्रिख सीतापुर-** तहसील मिश्रिख में अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया । तथा मुख्य मंत्री के दीर्घायु स्वास्थ एवं सफल जीवन की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने आशा व्यक्त की है । कि प्रदेश को आगे भी उनका कुशल नेतृत्व मिलता रहेगा। इस अवसर पर अधिवक्ता बृजलाल चौधरी, सुधीर शुक्ल राना, अकरम खान, सौरभ सक्सेना, नरेंद्र प्रताप सिंह, भाष्कर पाण्डेय, गौरव वाजपेयी, प्रेम प्रकाश राजवंशी, पुष्पेंद्र गुप्ता, सत्यप्रकाश अर्कवंशी, गोविंद प्रसाद राजवंशी, अजय पाण्डेय, जय प्रकाश शुक्ल, सूरज शुक्ल, सोनू कुमार, अमित कुमार सहित अनेक अधिवक्ताओं ने मुख्य मंत्री के जन्मदिन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

### विश्व पर्यावरण दिवस पर शहीद पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

**बिसवां/ सीतापुर-** पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, बिसवां के तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तहसील परिसर स्थित शहीद पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी सुश्री आकांक्षा गौतम, तहसीलदार अनिल कुमार तथा लॉयर्स एसोसिएशन बिसवां के अध्यक्ष आनंद कुमार मेहरोत्रा जी की गरिमामयी उपस्थिति में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण की आवश्यकता पर बल देते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संघ के सचिव नागेंद्र प्रताप, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेंद्र कुमार बाजपेई,अशोक कुमार वर्मा, राजकिशोर यादव, रामकृष्ण दीक्षित,सुशील शुक्ला, प्रमोद कुमार मिश्रा,अभय अवस्थी,ओम जी,मोहित कश्यप, नावेद सिद्दीकी सहित अनेक वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी उपस्थित जनों ने पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं हरित वातावरण उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया।

# करोड़ों की सरकारी स्कूल भूमि पर निजी सौदे का आरोप रिकॉर्ड में नहीं दर्ज विद्यालय

**● नगर पंचायत अभिलेख में 1.75 लाख कर बकाया**

**जमीन बचाने को उठी जांच की मांग**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लालगंज (रायबरेली)।** कस्बे के घोषियाना मोहल्ले स्थित राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का पुराना भवन इन दिनों विवादों में घिर गया है। आरोप है कि विद्यालय की करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि को निजी नाम कराने और बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह भूमि वर्षों पहले शिक्षा के उद्देश्य से दान की गई थी। माना जाता है कि मारवाड़ी समाज के शंकरलाल और शांतिलाल ने वर्ष 1937 के आसपास यह जमीन विद्यालय के लिए दी थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। पुराने अभिलेख उर्दू भाषा में हैं जिनका अनुवाद कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां पहले सरकारी प्राथमिक विद्यालय संचालित हुआ। बाद में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चला। वर्ष 2008 में विद्यालय के इंटर कॉलेज बनने के बाद उसे नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से पुराना भवन खाली पड़ा है। वर्तमान में इसका उपयोग चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ और अन्य सार्वजनिक कार्यों में किया जाता है। परिसर में स्थित हनुमान मंदिर भी स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय परिसर में विधायक निधि व जनसहयोग से अतिरिक्त कमरे भी बनवाए गए थे। इस कारण यह परिसर सामाजिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जिला योजना समिति के सदस्य व सभासद राघवेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि मामले की जांच में यह बात सामने आई है कि तहसील के राजस्व

अभिलेखों में विद्यालय का नाम दर्ज नहीं है। वहीं नगर पंचायत के रिकॉर्ड में भवन दर्ज है और उस पर लगभग 1.75 लाख रुपये गृहकर बकाया बताया गया है। लोगों का कहना है कि करीब 12 बिस्वा भूमि की वर्तमान बाजार कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है। सूत्रों के मुताबिक 22 मई 2026 को इस संपत्ति को लेकर 10 लाख रुपये का एक एग्रीमेंट भी किया गया है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से जांच कराकर भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अवैध कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।

### खम्भा गाड़ने को लेकर दो पक्षों मारपीट, पांच घायल

**लालगंज (रायबरेली)।** कोतवाली क्षेत्र के पूरेअधीन मजरे पलिया बिरसिंहपुर गांव में बिजली का पोल गाड़ने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के पांच लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव निवासिनी यशोदा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके खेत की मेड़ में लगा बिजली का पोल टूट गया था। उसे दोबारा गाड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि बृहस्पतिवार शाम गांव के ही रामचंद्र, सूरज, संजय, धर्मेंद्र और अनिल कुमार अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर पहुंचे। वहां गाली गलौज करते हुए उसके ससुर मोतीलाल के साथ मारपीट करने लगे। शोर सुनकर परिवार के विनोद, मनीष, संजय और बबली बचाने पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें भी पीट दिया। मारपीट में चारों लोग घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पांच नामजद और चार पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

## धेमाजी के डेकापाम में रेलवे लाइन पर हुए भयानक हादसा, मौके पर एक महिला की मौत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**असम धेमाजी।** आज दुपहर 2 बजे असम धेमाजी जिले की डेकापाम में लिडू- मुर्कोंगसेलेक डेमो ट्रेन पार करते समय एक भयानक दुर्घटना हुई। खबर अनुसार एक बोलने वाहन ने खुले रेल क्रॉसिंग पार करने की कोशिश करते समय ट्रेन ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतना भयानक था कि बोलेनो वाहन को 50 मीटर तक घसीट कर ले गया। मौके ही बर्दातात पर रीवा उपाधि के एक महिला की गाड़ी के अंदर ही मृत्यु हो जाते है। गंभीर रूप से घायल चालक को स्थानीय लोगों की मदत से अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी चालक ओर सवारी दोनों नज़दीक के अरुणाचल प्रदेश के ताजगांव के निवासी है। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को रेल लाइन से हटाकर लाइन मुक्त कर ट्रेन आवागमन के व्यवस्था किया गया। लोगों ने रेल विभाग से लिडू- मुर्कोंगसेलेक ट्रेन का अनियमित समय पर सवाल खड़े कर रहे ओर खुले क्रॉसिंग को बंद करने के लिए विभाग से अपील की है।

## विश्व पर्यावरण दिवस पर बम्हनावा केंद्र में सामूहिक पौधारोपण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**रेउसा ,बम्हनावा —** विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लॉक रेउसा के बम्हनावा स्वास्थ्य केंद्र में सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र की सीएचओ, एएनएम, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल की। सुबह करीब 10 बजे केंद्र परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने एक स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यकर्ताओं ने एक पौधे को सामूहिक रूप से रोपित किया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं बल्कि निरंतर प्रयास का विषय है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर पेड़ लगाने, जल संरक्षण और स्वच्छता जागरूकता फैलाने जैसे

कार्यों को बढ़ावा देने की बात कही। सीएचओ शिल्पी सिंह ने कहा, 'विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबका यह छोटा सा प्रयास प्रकृति के संरक्षण में हमारी भागीदारी को दर्शाता है। आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी बहनों के साथ मिलकर हम समुदाय को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। ' यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इन कर्मियों ने सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए अन्य नागरिकों से भी पौधारोपण में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

### 28 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियोग पंजीकृत

**रायबरेली-** जिलाधिकारी हर्षिता माथुर एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के आदेशानुसार, संयुक्त आबकारी आयुक्त लखनऊ जोन एव उप आबकारी आयुक्त लखनऊ प्रभार के कुशल मार्गदर्शन मे अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध जारी विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत जिला आबकारी अधिकारी के कुशल नेतृत्व में ,आबकारी निरीक्षक क्षेत्र- 3 की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश की कार्यवाही की गयी। टीम द्वारा तहसील लालगंज के थाना खीरों अंतर्गत ग्राम महारानी गंज एवं नन्दा खेड़ा में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डों/संदिग्ध घरों पर दबिश की कार्यवाही की गई। दबिश के दौरान 28 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा लगभग 150 किलोग्राम लहन बरामद कर मौके पर नष्ट करते हुए 02 अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किये गए ।जिले में अवैध शराब के निर्माण एव बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेंगी।

## विश्व पर्यावरण दिवस पर आईएमआरटी बिजनेस स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** राजधानी लखनऊ में 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आईएमआरटी बिजनेस स्कूल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी श्री राजीव कुमार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास तथा वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अपने संबोधन में श्री कुमार ने पर्यावरणीय जागरूकता के वैश्विक इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन ने पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक विमर्श का प्रमुख विषय बनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय नीतियों एवं सहयोग की मजबूत नींव रखी। उन्होंने भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि न्यायालय के विभिन्न निर्देशों और हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप अनेक पर्यावरणीय कानूनों एवं नीतियों को मजबूती मिली है। उन्होंने भारतीय संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (डीपीएसपी) तथा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज व्यवसायिक संस्थान पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं तथा अपनी कार्यप्रणाली में सतत विकास के सिद्धांतों को शामिल कर रहे हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण बताते हुए उन्होंने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने दैनिक जीवन में 'रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल' के सिद्धांतों को अपनाने तथा 'यूज़ एंड थ्रो' संस्कृति से दूर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका कुमार ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। यह संवादात्मक सत्र अत्यंत

ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहा। इस अवसर पर आईएमआरटी बिजनेस स्कूल के चेयरमैन डी.आर. बंसल, आईएफएस (सेवानिवृत्त) तथा निदेशक प्रो. शिल्पिका पांडेय ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से आईएमआरटी बिजनेस स्कूल ने पर्यावरणीय जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया और विद्यार्थियों को हरित एवं सुरक्षित भविष्य के निर्माण हेतु प्रेरित किया। 'आज प्रकृति की रक्षा करें, ताकि कल का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो। '

## स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ में एक संगोष्ठी का आयोजन संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** राजधानी लखनऊ में 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस-2026 के अवसर पर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (एसएमएस), लखनऊ में एक विशेष व्याख्यान एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष की वैश्विक थीम 'Inspired by NatureÑ For Climate, For Our Future' की पृष्ठभूमि में किया गया, जिसमें प्रकृति से प्रेरणा लेकर जलवायु संरक्षण एवं भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं प्रख्यात पर्यावरणविद् प्रो. भरत राज सिंह, महानिदेशक (तकनीकी), एसएमएस लखनऊ ने कहा कि वर्तमान समय में मानवता को पर्यावरणीय चुनौतियों का गंभीरता से पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वनों की अंधाधुंध कटाई, हाइड्रोकार्बन ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन, ग्लेशियरों का तीव्र पिघलना तथा विनाशकारी चक्रवातों और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जलवायु परिवर्तन की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक गर्मी की लहरें (हीटवेव), अनियंत्रित वर्षा, तेज हवाएं एवं धूल भरी आंधियां जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जो मानव जीवन एवं जैव विविधता दोनों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। प्रो. सिंह ने बताया कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है। संस्थान द्वारा व्यापक वृक्षारोपण अभियान, रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से 100 प्रतिशत हरित परिसर की स्थापना, अपशिष्ट प्रबंधन तथा जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण (Water Recharge) जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इन उत्कृष्ट प्रयासों के लिए संस्थान को तीन बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त हो चुका है। उन्होंने सभी से इन प्रयासों को आगे भी जारी रखने का आह्वान किया। संस्थान के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शरद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भविष्य में

संस्थान शोध एवं नवाचार के माध्यम से ऐसे समाधान विकसित करने की दिशा में कार्य करेगा, जिनसे प्रदूषण-मुक्त वायु और स्वस्थ जीवन के लिए बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। एसोसिएट डायरेक्टर, डॉ. धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण किसी विकल्प का विषय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। डीन-छात्र कल्याण, डॉ. पी.के. सिंह ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनसमुदाय से अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का आग्रह करते हुए कहा कि पेड़-पौधे ही स्वच्छ एवं सांस लेने योग्य वायु प्रदान करते हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से कम से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की।

## विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**सीतापुरः** मेरा युवा भारत, सीतापुर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयुक्त तत्वावधान में सैक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया और 'पर्यावरण बचाओ, धरती बचाओ' के नारे लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व, इतिहास तथा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता, स्पेल बी प्रतियोगिता और फोटोग्राफी प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में अर्पिता सिंह ने प्रथम स्थान, देवराज शुक्ला ने द्वितीय स्थान तथा शोभित अवस्थी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सिद्धार्थ राठौर प्रथम, ऋतिक गुप्ता द्वितीय और अपर्णा ठाकुर तृतीय स्थान पर रहे। स्पेल बी प्रतियोगिता में आयुषी ने प्रथम, अंशुल ने द्वितीय तथा आदित्य ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शशिकला मिश्रा, डॉ. राजेश श्रीवास्तव तथा असिस्टेंट प्रोफेसर उमंग अरोड़ा द्वारा किया गया। विजेताओं को पुरस्कार व प्रमाण-पत्र डॉ. फादर सजिमोन फिलिप तथा जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा द्वारा प्रदान किए गए। अंत में जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना, सीतापुर तथा सैक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज का धन्यवाद ज्ञापित किया और सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास साबित हुआ।

### वृक्ष धरा का भूषण हैं:-कमाल अहमद सिद्दीकी

**बिसवां (सीतापुर)।** शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिसवां वन रेंज में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन निकटवर्ती भिनैनी गांव में किया गया जिसमें क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा द्वारा त्रिवेनी वृक्षों का रोपण किया गया साथ ही भिनैनी गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से विधायक निर्मल वर्मा एवं वन क्षेत्राधिकारी अहमद कमाल सिद्दीकी द्वारा लोगों को जूट एवं कपड़े के थैलों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान एवं अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा भी शोभाकार, औषधीय एवं फलदार पौधों का रोपण किया गया।आज ही 'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियान की शुरुआत भी की गई। वन क्षेत्राधिकारी ने पर्यावरण बचाने के लिए सभी से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक के उपयोग से बचें। नदियों, तालाबों को प्रदूषणमुक्त रखें तथा जल संरक्षण करें यह जीवन के लिए बहुत जरूरी है।

## लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में बड़े पैमाने पर फेरबदलः पारदर्शी तबादला नीति पर उठे सवाल, क्या रसूखदारों को मिल रहा संरक्षण?

**● .....पश्चिमी जोन में उपनिरीक्षकों के ट्रांसफर से जहां जनता में कानून व्यवस्था सुधरने की उम्मीद जगी, वहीं बाजार खाला कोतवाली में वर्षों से जमे सिपाहियों को लेकर प्रशासनिक निष्पक्षता पर खड़े हुए गंभीर सवाल**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से एक बार फिर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी जोन) द्वारा 04 जून 2026 को जारी की गई आधिकारिक स्थानांतरण सूची के तहत कई उपनिरीक्षकों और मुख्य आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनातियों पर भेजा गया है। उच्च अधिकारियों के इस कदम का स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्ध वर्ग ने खुले दिल से स्वागत किया है। जनता का मानना है कि लंबे समय से एक ही जगह जमे अधिकारियों के हटने से न सिर्फ थानों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, बल्कि आम जनमानस में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। इसे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बेहद सकारात्मक और कड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि, जहां एक तरफ इन तबादलों को लेकर पुलिस महकमे और जनता में संतोष का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी प्रक्रिया ने विभागीय नीति और उसकी निष्पक्षता पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। स्थानीय सूत्रों और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों का दावा है कि लखनऊ की सुप्रसिद्ध बाजार खाला कोतवाली में कई ऐसे महिला और पुरुष सिपाही (आरक्षी) तैनात हैं, जिन पर यह स्थानांतरण नीति पूरी तरह बेअसर साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि ये खास पुलिसकर्मी देश में लगे कोरोना लॉकडाउन के समय से ही, यानी पिछले कई वर्षों से, इसी एक थाने में 'अंगद की तरह पैर जमाए' बैठे हैं। जबकि नियमतः एक निश्चित समयावधि के बाद पुलिसकर्मियों का पटल या थाना परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इन सिपाहियों के मामले में नियमों को ताक पर रख दिया गया है।

**जनता का सवालः** 'जब हर स्तर पर नियमित और पारदर्शी तबादले किए जा रहे हैं, तो बाजार खाला कोतवाली में बरसों से जमे इन खास पुलिसकर्मियों पर मेहरबानी की वजह क्या है? '

इस विसंगति को लेकर अब स्थानीय जनता और महकमे के भीतर ही तीखी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोग सीधे तौर पर उच्च अधिकारियों की मजबूरी और मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर इन पुलिसकर्मियों को वर्षों से एक ही थाने में बनाए रखने के पीछे क्या कोई बड़ा राजनीतिक दबाव काम कर रहा है, या फिर इसके पीछे किसी रसूखदार का प्रशासनिक वर्चस्व है? स्थानीय लोगों का स्पष्ट मानना है कि यदि शासन और प्रशासन की तबादला नीति वास्तव में पारदर्शी और ईमानदार है, तो इसे बिना किसी भेदभाव के सभी छोटे-बड़े पुलिसकर्मियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। 'अपनों को राहत और दूसरों को आफत' वाली यह नीति पुलिस की छवि को धूमिल करती है। अब देखना यह होगा कि क्या लखनऊ पुलिस के आला अधिकारी इस विसंगति का संज्ञान लेकर कोई ठोस और निष्पक्ष कदम उठाते हैं, या फिर जनता के ये सुलगते सवाल हमेशा की तरह फाइलों के नीचे दबकर रह जाएंगे।

## जीत वेलफेयर फाउंडेशन व कलम शक्ति ट्रस्ट ने चलाया वृहद वृक्षारोपण अभियान

**● 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लालगंज, रायबरेली।** विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जीत वेलफेयर फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश, कलम शक्ति ट्रस्ट एवम् जागेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में लालगंज क्षेत्र में वृहद वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत नवीन मंडी स्थल एवं कोतवाली परिसर, लालगंज सहित विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 09 बजे हुआ, जिसमें दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों, समाजसेवियों एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए बड़ी संख्या में पौधे रोपे। इस अवसर पर 'एक व्यक्ति-एक पौधा' तथा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया। जीत वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक/अध्यक्ष जितेन्द्र सविता (पत्रकार) ने कहा कि संस्था विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल जीवन का आधार हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करने का सबसे प्रभावी माध्यम भी हैं। वहीं कलम शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक/अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह (पत्रकार) ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करे।

उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यापक वृक्षारोपण अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी लक्ष्य को साकार करने तथा पर्यावरण संरक्षण की जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थाओं द्वारा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अभियान के दौरान उपस्थित लोगों ने पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और स्वच्छ भविष्य के संदेश के साथ हुआ। संस्थाओं के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाकर उसका संरक्षण करे, तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और हरित भारत प्रदान किया जा सकता है।

# संक्षिप्त खबरें

## हर्ष फायरिंग में महिला की मौत में बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह दोषी करार, 9 जून को होगी सजा पर सुनवाई

**दिल्ली।** राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2018 में नव-वर्ष समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला की मौत के मामले में बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 (गैर-इरादतन हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। मामले में सजा की अवधि पर नौ जून को सुनवाई होगी। अदालत ने राजू सिंह की पत्नी, रमेंद्र सिंह और राणा राजेश सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। घटना के अनुसार, 31 दिसंबर 2018 की रात नई दिल्ली के मंडी गांव स्थित रोज फार्म में आयोजित नववर्ष पार्टी के दौरान विकास गुप्ता अपनी पत्नी अर्चना गुप्ता और बेटी के साथ मौजूद थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, रात करीब 12 बजे उन्होंने राजू सिंह और उनके चालक हरि सिंह को हथियारों से हवाई फायरिंग करते देखा। कुछ मिनट बाद फिर फायरिंग हुई, जिसके बाद अर्चना गुप्ता अचानक जमीन पर गिर गईं। उनके चेहरे पर खून था और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस जांच में यह सामने आया कि पार्टी के दौरान चली गोली से अर्चना घायल हुई थीं और घटनास्थल पर पड़ा खून भी साफ कर दिया गया था। एक जनवरी 2019 को फतेहपुर बेरी थाने में पहले हत्या के प्रयास, साक्ष्य मिटाने और आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान घटनास्थल से .22 बोर के दो इस्तेमाल किए गए कारतूस बरामद हुए। राजू सिंह के घर से भी हथियार और कारतूस बरामद किए गए, जबकि उनके चालक हरि सिंह के घर से एक .315 बोर राइफल और अन्य सामग्री मिली थी। जांच में यह भी सामने आया कि फायरिंग के बाद राजू सिंह और उनका चालक मौके से फरार हो गए थे। दोनों को दो जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के फाजिलनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय राजू सिंह के पास से .22 बोर की पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। उपचार के दौरान तीन जनवरी 2019 को अर्चना गुप्ता की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा हटाकर हत्या का मामला दर्ज किया। एम्स में हुए पोस्टमार्टम में डाक्टरों ने स्पष्ट किया कि अर्चना की मौत सिर में गोली लगने से हुई चोट के कारण हुई थी। उल्लेखनीय है कि 30 अक्टूबर 2023 को अदालत ने राजू सिंह की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ धारा 304 (भाग-2) और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए थे।

## डाक अधीक्षक द्वारा किया गया वृक्षारोपण

**सीतापुर-** डाक घर के प्रांगण में डाक अधीक्षक राजेश कुमार तिवारी जी के करकमलों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया तथा सभी को अधिकाधिक वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया गया।

# कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर की बढ़ीं मुश्किलें, 8 जून को दाखिल करेंगे अग्रिम जमानत याचिका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**पटना।** बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान (खान सर) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पटना के कदमकुआं क्षेत्र स्थित कोचिंग संस्थान से जुड़े फायरिंग मामले में दर्ज एफआईआर के बाद कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। ताजा घटनाक्रम में खान सर ने फिलहाल अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करने का फैसला लिया है और 8 जून को अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि उनके मुवक्किल फिलहाल पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की जाएगी। अदालत के निर्णय के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र संस्थान के बाहर एकत्र हो गए थे और पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा था। इस प्रकरण में पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं, खान सर के समर्थकों का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत विवाद में घसीटा जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मामले ने शिक्षा जगत और छात्र समुदाय में व्यापक चर्चा पैदा कर दी है। अब सबकी निगाहें 8 जून को दाखिल होने वाली अग्रिम जमानत याचिका और अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत के आदेश के बाद मामले की दिशा काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।

## पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में अल्का लांबा दोषी करार

**दिल्ली।** महिला आरक्षण की मांग को लेकर वर्ष 2024 में हुए संसद घेराव प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी करार दी गई कांग्रेस नेता अलका लांबा को अदालत ने शनिवार को परिवीक्षा (प्रोबेशन) का लाभ देते हुए एक वर्ष के लिए अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने अलका लांबा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। मामले में अदालत ने 25 मई को अलका लांबा को दोषी करार दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि उन्होंने निषेधाज्ञा के आदेशों की अनदेखी की और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान लांबा की ओर से अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन पर रिहा किए जाने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने उन्हें लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, लागू आदेश की अवहेलना करने और सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के आरोपों में दोषी ठहराया था।

## तिहाड़ जेल में डर रहे संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, कोर्ट में लगाई गुहार- हमारे ऊपर हो सकता है हमला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**दिल्ली।** पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संसद सुरक्षा चूक मामले में तीन आरोपितों ने जेल के अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। आरोपितों ने दावा किया कि उन्हें अन्य विचाराधीन कैदियों से हमले का खतरा है और उन्हें दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने उनकी अर्जी पर संबंधित जेल प्रशासन को कानून के मुताबिक उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने मामले से जुड़े चार आरोपितों की न्यायिक हिरासत भी आठ जुलाई तक बढ़ा दी। मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। सुनवाई के दौरान आरोपित मनोरंजन डी, ललित झा और सागर शर्मा ने अदालत को बताया कि उन्हें जेल में सुरक्षा संबंधी खतरा महसूस हो रहा है। मनोरंजन डी और ललित झा फिलहाल जेल नंबर-आठ में बंद हैं, जबकि सागर शर्मा जेल नंबर-एक में है। तीनों ने अदालत से उन्हें जेल नंबर-चार में स्थानांतरित करने की मांग की। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जेल में स्थानांतरण का विषय जेल प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद अदालत ने संबंधित जेल अधिकारियों को आरोपितों की याचिकाओं पर नियमों के अनुसार फैसला लेने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सभी आरोपित अदालत में पेश हुए। यह मामला 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक से जुड़ा है। उस दिन दो आरोपित विजिटर गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और पीले रंग का धुआं छोड़ने वाले कैनिस्टर का इस्तेमाल किया था। इसी दौरान संसद भवन के बाहर भी दो अन्य लोगों ने नारेबाजी करते हुए पीला धुआं छोड़ा था।

# लंबे समय से लंबित मांग, दुल्लभछड़ा-बदरपुर ट्रेन को सिलचर तक विस्तारित करने की जोरदार अपील

**● पुरानी मीटर गेज समय-सारिणी बहाल करने की मांग, शाम की ट्रेन सिलचर तक चलाने हेतु रेल मंत्री से हस्तक्षेप की मांग**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**श्रीभूमि-** जिले के दुल्लभछड़ा-बदरपुर रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेन को सिलचर तक विस्तारित करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराज़गी और निराशा बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मीटर गेज समय में यह ट्रेन दोपहर लगभग 2:30 बजे दुल्लभछड़ा से चलकर रात लगभग 7:30 से 8:00 बजे के बीच सिलचर पहुंचती थी। इससे कर्मचारी, व्यापारी, छात्र-छात्राएं और आम यात्रियों को काफी सुविधा मिलती थी। वर्तमान में 55689 नंबर की ब्रॉड गेज ट्रेन केवल दुल्लभछड़ा से बदरपुर तक ही सीमित है, जिससे सिलचर जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि पुरानी समय-सारिणी के अनुसार शाम की ट्रेन को दुल्लभछड़ा से चलाकर सिलचर तक विस्तारित किया जाए, तो यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही बराक घाटी की परिवहन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। स्थानीय नागरिकों और बुद्धिजीवियों ने रेलवे मंत्रालय से आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए और जनहित में आवश्यक कदम उठाए जाएं। उनका मानना है कि मीटर गेज समय-सारिणी के आधार पर यदि नई योजना बनाई जाती है, तो दुल्लभछड़ा, बदरपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सिलचर से बेहतर और सुगम संपर्क मिल सकेगा। लोगों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी इस विषय में हस्तक्षेप करने की अपील की है, ताकि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र उचित निर्णय ले सके।

# जिले के बदरपुर एन.सी. कॉलेज ऑडिटोरियम परिसर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जागरूकता सभा व हस्ताक्षर अभियान

**● 300 से अधिक लोगों ने किए हस्ताक्षर, न्याय के लिए आंदोलन को और मजबूत करने का आह्वान**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**श्रीभूमि-** असम के बराक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को मजबूत करने के उद्देश्य से हाईकोर्ट बेंच मांग कार्यान्वयन समिति, कछार जिला समिति के तत्वावधान में 6 जून शनिवार को बदरपुर एन.सी. कॉलेज ऑडिटोरियम परिसर में जागरूकता सभा एवं जन हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, राजनीतिक प्रतिनिधियों, समाजसेवियों, छात्र-छात्राओं तथा विभिन्न वर्गों के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 2 बजे जागरूकता सभा से हुआ। सभा में समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार साहा, कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रो. अरुण कुमार सेन, प्राचार्य पार्थ सारथी दास, सामयिक प्रसंग पत्रिका के संपादक तैमूर राजा चौधरी, अधिवक्ता सुमिता पोद्दार, विश्व बरुण बरुआ, धर्मानंद देव, भाजपा नेता दीपक देव, प्रो. जयनाल आबेदीन तापादार, अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती एवं तुहिना शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कटीगड़ा के विधायक कमलाक्ष्य पुरकायस्थ कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने लिखित संदेश भेजकर हाईकोर्ट बेंच की मांग का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। उनका संदेश सभा में पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि यह मांग बराक घाटी के लाखों लोगों की न्यायसंगत और जनहित से जुड़ी पुरानी मांग है तथा न्यायिक सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए स्थायी बेंच की स्थापना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्यों के लिए लोगों को गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, धन और श्रम की हानि होती है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थायी बेंच स्थापित होने से न्याय प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और किफायती होगी। स्वागत भाषण में प्रो. अरुण कुमार सेन ने कहा कि न्याय प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और यह मांग पूर्णतः न्यायसंगत है। समिति अध्यक्ष ध्रुव कुमार साहा ने कहा कि लगभग 40 लाख आबादी वाले बराक घाटी क्षेत्र के लिए हाईकोर्ट बेंच आज समय की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि न्यायिक मामलों के लिए लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अधिवक्ता धर्मानंद देव की तथ्यपरक पावर प्वाइंट प्रस्तुति रही। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों और न्यायिक व्यवस्था के विकासक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि फोर्ट विलियम कोर्ट से लेकर शिलांग और गुवाहाटी हाईकोर्ट तक की न्यायिक यात्रा के बीच बराक घाटी में स्थायी बेंच की आवश्यकता स्पष्ट रूप से बनती है। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने इस मांग को जनहित से जुड़ा बताते हुए सरकार से शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि न्याय तक समान पहुंच का जनआंदोलन है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मौनिता नाथ ने किया तथा प्रश्नोत्तर सत्र का संचालन अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती ने किया। अंत में प्रो. जयनाल आबेदीन तापादार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसके बाद शाम 5 बजे जन हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ, जिसमें महिला-पुरुष, छात्र-छात्राएं, शिक्षक, व्यापारी एवं विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों के अनुसार इस अभियान में 300 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर समर्थन व्यक्त किया। समिति ने बताया कि भविष्य में भी इस मांग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसी क्रम में आगामी 8 जून को सोनाई एम.सी. कॉलेज परिसर में भी जागरूकता सभा एवं हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने लोगों से अपील की कि वे इस जनआंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाएं और न्यायसंगत मांग को मजबूत करें। समिति ने विश्वास व्यक्त किया कि जनसमर्थन के बल पर यह लंबित मांग एक दिन अवश्य पूरी होगी।

# जर्मनी की राजनीति में बड़ा झटका: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट गंवाने पर बढ़ी सरकार की मुश्किलें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**बर्लिन।** यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले जर्मनी को इस सप्ताह एक बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) की अस्थायी सदस्यता के चुनाव में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, जिससे देश की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में जर्मनी आवश्यक समर्थन जुटाने में असफल रहा। पश्चिमी यूरोपीय समूह की सीटों के लिए हुए चुनाव में ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल को सफलता मिली, जबकि जर्मनी पहली बार इस तरह की महत्वपूर्ण हार का सामना कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के वर्षों में जर्मनी की विदेश नीति, विशेषकर यूक्रेन युद्ध, इज़राइल समर्थन और विदेशी सहायता बजट में कटौती जैसे मुद्दों ने कई देशों को उससे दूर कर दिया। यही कारण रहा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों का अपेक्षित समर्थन जर्मनी को नहीं मिल सका। जर्मनी के विदेश मंत्री और सरकारी अधिकारियों ने इस परिणाम पर निराशा व्यक्त की है। सरकार का कहना है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखेगी और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में योगदान देती रहेगी। हालांकि विपक्षी दलों ने इसे सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया है और विदेश नीति की समीक्षा की मांग की है। इस हार के बाद जर्मनी में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप और वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों के बीच संतुलन बनाने में जर्मनी अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाया। इसके चलते उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को झटका लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना केवल एक चुनावी हार नहीं बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत भी है। आने वाले समय में जर्मनी को अपनी विदेश नीति, विकास सहयोग कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को और मजबूत करना होगा ताकि वह विश्व मंच पर अपनी प्रभावशाली भूमिका बनाए रख सके।

# Pre-SIR के तहत वोटर मैपिंग के लिए जिले के सभी 400 पोलिंग बूथ पर स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे

**● वोटर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने बूथ पर पहुंचकर मैपिंग करवा सकेंगे- विराज एस. तिड़के**

**इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बताए गए 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दी गई है।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**मालेरकोटला-** चीफ इलेक्शन ऑफिसर, पंजाब, चंडीगढ़ के निर्देशानुसार, मालेरकोटला जिले के असेंबली हलके-105 मालेरकोटला और असेंबली हलके-106 अमरगढ़ के सभी 400 पोलिंग बूथ पर कल, 07 जून, 2026 (रविवार) को मौजूदा वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटरों को साल 2003 की वोटर लिस्ट से मैप करने के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे।यह जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर-कम-डिप्टी कमिश्नर विराज एस. तिड़के ने बताया कि कैंप के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) उपायुक्त ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले 11 प्रकार के दस्तावेजों को मंजूरी दी है। इनमें सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी/ एससी/ एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी रिकॉर्ड, परिवार रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि या घर आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि आधार कार्ड के संबंध में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने बूथों पर पहुंचने और मैपिंग प्रक्रिया को सफल बनाने की अपील की।

## चोरी के मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का मोबाइल और नकदी बरामद

**प्रयागराज।** जार्जटाउन पुलिस ने चोरी के एक मामले में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल फोन एवं नकद रुपये बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस के अनुसार थाना जार्जटाउन में पंजीकृत मु0अ0सं0-95/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित मामले की विवेचना के दौरान पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना जार्जटाउन पुलिस ने के.पी. बस स्टैंड के पास से दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अजीत पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम सरपतीपुर, थाना सरायइनायत, जनपद प्रयागराज तथा सूरज यादव पुत्र अतर सिंह यादव निवासी जुनैदपुर, थाना सरायइनायत, जनपद प्रयागराज के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की घटना से संबंधित सामान बरामद किया गया।

# 25 दिनों से अंधेरे में उपभोक्ता: 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर 40-45 कनेक्शन

**● बिल पूरा लेकिन बिजली शून्य; मुख्यमंत्री जी, इसका जिम्मेदार कौन?**

**बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही या सिस्टम की नाकामी?**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**गोण्डा।** जनपद गोण्डा के विकासखंड रुपईडीह अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र खरगूपुर के क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम माथेडीह से लेकर भवानीपुर उपाध्याय चौराहे तक, आर्यनगर-महराजगंज मार्ग के किनारे रहने वाले विद्युत उपभोक्ता पिछले लगभग 25 दिनों से भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भीषण गर्मी और उमस के बीच दर्जनों परिवारों के घरों में अंधेरा पसरा हुआ है, जबकि अधिकांश उपभोक्ताओं का विद्युत बिल भी बकाया नहीं है।ग्रामीणों का आरोप है कि यह समस्या किसी एक दिन की तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि विभागीय उदासीनता और वर्षों से चली आ रही अनदेखी का परिणाम है। लोगों का कहना है कि गांव में स्थापित 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर लगभग 40 से 45 कनेक्शन संचालित किए जा रहे हैं, जिसके कारण लगातार ओवरलोड की स्थिति बनी रहती है। सवाल यह है कि जब ट्रांसफार्मर की क्षमता सीमित थी, तो उस पर इतने अधिक कनेक्शन स्वीकृत क्यों किए गए?प्रभावित उपभोक्ताओं में रामकुमार पुत्र जयराम (कनेक्शन संख्या 9575540100), रामप्रसाद पुत्र जयराम, भगवान चरण, लाला, घनश्याम, छोटे मौर्य सहित एक दर्जन से अधिक परिवार शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे हर महीने समय से बिजली बिल जमा करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें न तो पर्याप्त बिजली मिल रही है और न ही उनकी शिकायतों का समाधान।

**बिल पूरा, बिजली गायब — आखिर क्यों?**

ग्रामीणों का कहना है कि जब पिछले 25 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है, तो आखिर उनसे किस बात का बिल लिया जाएगा? यदि बिजली का उपयोग ही नहीं हुआ, तो उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ डालना कैसे उचित माना जा सकता है?लोगों का आरोप है कि विभाग बिल वसूली में तो पूरी तत्परता दिखाता है, लेकिन जब उपभोक्ताओं को सुविधा देने की बात आती है, तो जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।

**कई शिकायतें, फिर भी नहीं हुआ समाधान**

ग्रामीणों के अनुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने और बिजली आपूर्ति सुचारू कराने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिणामस्वरूप बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, पेयजल संकट गहरा रहा है और बुजुर्गों व महिलाओं को भीषण गर्मी में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

**मुख्यमंत्री जी, इसका जिम्मेदार कौन?**

प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बेहतर बिजली व्यवस्था पहुंचाने का दावा कर रहे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की बात करते हैं। ऐसे में गोण्डा जनपद के रुपईडीह विकासखंड अंतर्गत माथेडीह से भवानीपुर उपाध्याय चौराहे तक के उपभोक्ता पूछ रहे हैं–

मुख्यमंत्री जी, जब उपभोक्ता नियमित रूप से बिल जमा कर रहे हैं, तो 25 दिनों से बिजली से वंचित रहने का जिम्मेदार कौन है?

मुख्यमंत्री जी, 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर 40-45 कनेक्शन देने की अनुमति किसने दी?

मुख्यमंत्री जी, शिकायतों के बाद भी यदि समाधान नहीं हो रहा, तो जवाबदेही किसकी तय होगी?

**आंदोलन की चेतावनी**

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई और ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं बढ़ाई गई, तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और

उच्चाधिकारियों का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे।इस संबंध में एसडीओ पंकज राठौर ने बताया कि शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जेई खरगूपुर रवि वर्मा ने कहा कि समस्या की जानकारी है और जल्द समाधान का प्रयास किया जाएगा।

**जनता के सवाल**

25 केवीए ट्रांसफार्मर पर 40-45 कनेक्शन क्यों दिए गए?

25 दिनों से बाधित बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी है?

जब बिजली नहीं मिली तो बिल क्यों लिया जाए?

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

क्या विभागीय लापरवाही की जांच होगी?

माथेडीह और भवानीपुर उपाध्याय चौराहे के बीच रहने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि बिजली और जवाबदेही चाहिए। अब देखना यह है कि विभाग इन सवालों का जवाब देता है या फिर जनता को अपनी आवाज सड़क पर बुलंद करनी पड़ेगी।

# ओटीटी पर छा गई करिश्मा कपूर की 7 एपिसोड वाली सीरीज 'ब्राउन'

**● करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर राज कर रही है। इस सीरीज को IMDb से धांसू रेटिंग मिली है।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**नई दिल्ली।** दो साल बाद करिश्मा कपूर ओटीटी की दुनिया में लौटीं लेकिन वेब सीरीज लेकर। इस बार मेन लीड में करिश्मा थीं और नई कहानी के साथ ओटीटी पर धमाल मचा दिया। 24 घंटे के अंदर ही करिश्मा की सीरीज ओटीटी पर छा गई है। करिश्मा कपूर की नई वेब सीरीज ब्राउन है। रोमांटिक और ग्लैमरस रोल्स में नजर आने वालीं करिश्मा ने अपने करियर में पहली बार क्राइम थ्रिलर में ब्राउन जैसा किरदार निभाया हो। इस सीरीज में एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की जा रही है।

**क्या है ब्राउन सीरीज की कहानी?**

7 एपिसोड की सीरीज ब्राउन में करिश्मा कपूर पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रही हैं। सीरीज की कहानी रीटा ब्राउन (करिश्मा कपूर) की है जो शराब की लत से जूझ रही एक बदनाम डिटेक्टिव हैं और महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक सीरियल किलर की जांच कर रही हैं। अभीक बरुआ के नॉवेल 'सिटी ऑफ डेथ' पर आधारित यह सात एपिसोड की नॉयर सीरीज मर्डर मिस्ट्री के साथ-साथ मुख्य किरदार के दुख, ट्रॉमा और खुद को सुधारने की यात्रा को भी दिखाती है।

**किस ओटीटी पर है ब्राउन?**

अभिनय देव के निर्देशन में बनी वेब सीरीज ब्राउन में करिश्मा कपूर के अलावा जिशु सेनगुप्ता, अर्जुन सिन्हा, सोनी राजदान जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म में सलमान खान की सौतेली मां और एक्ट्रेस हेलेन भी हैं। यह सीरीज 5 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है। यह आते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में छा गई है।

**सीरीज को मिली धांसू रेटिंग**

करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन साल की सबसे टॉप रेटेड साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर बन गई है। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 9.3 रेटिंग मिली है। इसका ऐलान करते हुए जी5 ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'डार्क। जबरदस्त। बेमिसाल। ब्राउन ने फैन्स और क्रिटिक्स को दीवाना बना दिया है और इसकी रेटिंग्स खुद ही सब कुछ बयां कर रही हैं।'